

[1]

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 16/2026
(जीसीएमएस संख्या 2026/61)

निर्णय दिनांक:- 9-4-26

1. रूकमा देवी पत्नी मंगतूराम उर्फ मंगतराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 02, खींचड बास, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।
2. प्रहलाद पुत्र मंगतूराम उर्फ मंगतराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 02, खींचड बास, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।
3. गुरदयाल पुत्र मंगतूराम उर्फ मंगतराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 02, खींचड बास, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।
4. सरोज पुत्री मंगतूराम उर्फ मंगतराम पत्नी राजेश कुमार जाति जाट निवासी 23 पीबीएन, हनुमानगढ़।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजूवाला।

—रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 17-07-1998
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छतरगढ़ मु. बीकानेर।

उपस्थिति:-

1. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छतरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 17-07-1998 जिसके द्वारा अपीलांट के पिता/पति के नाम जारी आवंटन आदेश निरस्त किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।



राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटान के पिता एवं पति द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन विशेष आवंटन की श्रेणी में वाके चक 13 डीडब्ल्यूडी के मुरब्बा नम्बर 11/42 की 25 बीधा अनकमाण्ड आवंटन हेतु प्रस्तुत किया गया था एवं आवेदन के साथ राजस्थान का सद्भावी निवासी होने की वोटरलिस्ट, मूलनिवास प्रमाण पत्र, सद्भावी काश्तकार व भूमिहीन एवं भूमि की तस्दीक पेश की और उक्त दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी को भूमिहीन श्रेणी का मानते हुए सीलिंग सीमा तक भूमि आवंटन का पात्र मानकर पत्रावली आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 05.09.1997 कैम्प पूगल में पेश होने के आदेश होने पर आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में आवेदक को चक 13 डीडब्ल्यूडी के मुरब्बा नम्बर 11/42 की 25 बीधा अनकमाण्ड विशेष आवंटन हेतु राजपत्र में प्रकाशित होने एवं आवेदक द्वारा आवश्यक सबूत पेश होने से आवेदक को आवेदन हेतु पात्र होने की अभिशंषा दिनांक 05.07.1997 को की गई और विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तत्कालीन निर्धारित कीमत 71123/- रुपये पर आवंटित की गई और आदेश किया गया कि आवेदक को सूचित किया जावे कि आवंटित भूमि की कीमत जमा करवाने के लिए इस कार्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तु कर चालान प्राप्त करें एवं राशि जमा करवाकर चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें जिसकी सूचना आज दिनांक तक अपीलांटान को सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी नहीं की गई और एक तरफा बाला-बाला अपीलांटान को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध प्रार्थी को सूचित किये बिना आदेशिका पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होते हुए एवं आदेशिका दिनांक 11.06.1997 की पालना में कोई नोटिस जारी नहीं होने के बावजूद दिनांक 17.07.1998 को आवेदक का आवंटन 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई गई हैश का अंकन करते हुए आवंटन निरस्त कर दिया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांटान द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून, उसूल इन्साफ एवं रुहेदाद मिसल के है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के काबिल खारिजी के है। अपीलांटान के पिता एवं पति द्वारा कृषि भूमि वाके रोही चक 13 डीडब्ल्यूडी के मुरब्बा नम्बर 11/42



राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

तादादी 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो बाद जांच आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 05.09.1997 को आवंटन की अनुशंसा करने पर भूमि आवंटन की गई जिसे बाद पुलिस वेरिफिकेशन, चालान एवं पट्टा जारी करने बाबत कहा गया परन्तु उक्त आवंटन के आधार पर चालान जारी नहीं होने एवं अपीलांतान को जानकारी नहीं दिये जाने के कारण तगाम कार्यवाही एकतरफा बाला-बाला एवं अपीलांतान को सूचित किये बिना, सुनवाई का अवसर दिये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए किये जाने से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांतान को आवंटन अधिकारी द्वारा सम्बन्धित मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कोई नोटिस नहीं भिजवाया गया है और पत्रावली के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। अपीलांत द्वारा आवेदन के साथ समस्त औपचारिक दस्तावेज प्रस्तुत किये थे जिनके आधार पर ही आवंटी को उक्त आवंटन हुआ था फिर भी आवंटी को भूमि से महरूम करने के लिए जानबूझकर नोटिस जारी नहीं कर आवंटी को सूचना दिये बिना अपीलाधीन आदेश जारी कर कानूनी भूल की है। आवंटी हमेशा सभी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए तैयार व तत्पर रहा है। आवंटी ने आवेदन के समय समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण की है जो संलग्न पत्रावली है जिस पर बिना गौर किये अपीलाधीन आदेश पारित कर कानूनी भूल की है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत के पिता/पति को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांत के पिता/पति का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2017 पेज 209 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांत ने अपने

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर



कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन 35 प्रतिशत राशि के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।



प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते हैं। जहाँ तक मियाद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोजेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियाद घोषित की जाती है।

प्रकरण के गुणावगुण पर न्यायालय का अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 01-07-1997 को अपीलांट के पिता/पति को प्रश्नगत भूमि के आवंटन का पात्र घोषित किया गया।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह तथ्य भी साबित है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 05-07-1997 को अपीलांट के पिता/पति मंगतराम को प्रश्नगत भूमि चक 13 डीडब्ल्यूडी के मुरब्बा

राजस्थान अपील अधिकारी
बीकानेर

नम्बर 11/42 रकबा 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि के आवंटन की अभिशंसा की गई।

इसके पश्चात अपीलाधीन आदेश दिनांक 17-07-1998 द्वारा अपीलांट का आवंटन इस आधार पर निरस्त कर दिया कि अपीलांट द्वारा नोटिस के बावजूद 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई गई है।

प्रस्तुत मामलों में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।



इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जारी किये गये नोटिस का अवलोकन किया गया। उक्त नोटिस पर किसी प्रकार की तामील की सुनिश्चितता के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई सूचना अथवा चालान प्राप्त हुआ हो।

अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर के प्रकरण संख्या 4811/2014 निर्णय दिनांक 05-01-2026 उनवान साहबराम बनाम सरकार के निर्णय की प्रति पेश की जिसमें अभिनिर्धारित किया है कि " विचारण न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध एकपक्षीय होने से समर्थन योग्य नहीं है तथा ऐसे विधि विरुद्ध आदेश का समर्थन करने से अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।" माननीय न्यायालय द्वारा दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय को निरस्त करते हुए प्रकरण को पुनः रिमाण्ड किया गया था।

इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरडी 2017 पेज 209 का न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिसके अभिलिखित है कि:-


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Rajasthan Colonisation (Allotment & Sale of Government Land in IGNP Area) Rules, 1975 - R-23(2) Asstt. Commissioner allotted land and cost to be deposited by allottee- Allotment cancelled for non payment- Appellate Court rejected appeal of allottee - Revision before boar – Held - Land still vacant - Allottee could not deposit amount as no notice was received by him - In the interest of justice llotment regularized if allottee deposits cost with interest - Revision allowed on condition.

उक्त नजीर उक्त प्रकरण में पुर्णतया चस्पा होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं नजीर के प्रकाश में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत रकबा यदि किसी अन्य को आवंटित न हुआ हो, किसी सरकारी प्रयोजनार्थ आरक्षित न हो और अपीलांट 3 माह के भीतर समस्त बकाया राशि जमा करवा दे तो अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 9-4-26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)

राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
बिकानेर

